

राजस्थान में 1.42 लाख करोड़ के 32 नविश प्रस्तावों को मजूरी

चर्चा में क्यों?

2 अक्टूबर, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री नवास पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तीसरी बैठक में राज्य में 42 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नविश को प्रोत्साहन देने के लिये 32 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज की मजूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि इन्वेस्ट राजस्थान समिति की तैयारियों के लिये विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि यह समिति राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे राज्य में 32 हजार से अधिक लोगों के लिये रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
- बैठक में अनुमोदित प्रस्तावों में प्रमुख रूप से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एज्योर पावर प्राइवेट लिमिटेड, रनियू पावर प्राइवेट लिमिटेड आदि, प्लास्टिक एवं ग्लास निर्माण में असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में हीरो इलेक्ट्रिक वाहन, ओकाया ईवी प्राइवेट लिमिटेड के अतिरिक्त कपड़ा, खान एवं खनजि, पूड एवं बेवरेजेज, आतथिय, सीमेंट, ऑटो एवं ऑटो कंपोनेंट और कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण की परियोजनाओं को बोर्ड द्वारा मजूरी दी गई है।
- मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने नविश बढ़ाने के लिये अनेक महत्वपूर्ण नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया है, जैसे- राजस्थान में एमएसएमई नीति-2022, हस्तशिल्प नीति-2022, पर्यटन प्रोत्साहन नीति-2022, राजस्थान नविश प्रोत्साहन योजना (आरआईपीएस-2019), राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 एवं वन स्टॉप शॉप सिस्टम के माध्यम से नविशकों को अनेक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।
- राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के राज्य में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के प्रस्ताव लगातार मलि रहे हैं। इससे राजस्थान के औद्योगिक विकास को और मजबूती मिलेगी।
- मुख्यमंत्री गहलोत ने जैसलमेर संभाग में सीमेंट उद्योग के विकास की संभावनाओं के लिये अध्ययन के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग के लिये पर्याप्त कच्चा माल, जैसे- लाइमस्टोन आदि उपलब्ध है।